pay any tax or pay marginal tax, several thousand assessment records are required to be individually scrutinised. The time, efforts and expenditure to collect the information will not be commensurate with the results sought to be achieved.

(b) and (c) In view of the Budget secrecy; it would not be proper at this stage, to furnish information in respect of Budget proposals.

(d) No separate statistics regarding tax received from Public Sector companies are maintained. However, figures of Corporate Tax received during the last three years are as under:—

	(Rs. in crores)
1992-93	8889.24
1993-94	10060.06
1994-95	13821.00

Closure of Textile Mills in Ahmedabad

*331. SHRI AHMED PATEL:
SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether as a result of closure of textile mills in Ahmedabad some 40,000 workers have been rendered jobless;

(b) if so, what steps have since been taken for payment of statutory dues to them; and

(c) whether Gujarat Government had proposed that Union Government may take over the assets of these sick textile mills and revive them by pooling their resources and granting loans for payment of statutory dues to the workers; if so, Government's decision thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI KAMAL NATH): (a) to (c) According to the Minister of Industry the Government of Gujarat has submitted a proposal to the Ministry of Industry for grant of assistance from the National Renewal Fnnd for Area Regeneration Scheme for 19 closed textile mills under liquidation. The proposal envisages (inter-alia) take-over of the assets of these mills by the State Government, payment of legal dues to the 30,150 employees of the mills, retraining of jobless employees, incentive for area regeneration and utilisation of assets of closed mills, etc. The matter of payment of statutory dues or taking over of assets by the state Government, comes under the jurisdication of the state Government.

विभिन्न विमानपत्तनों से जब्त की गयी वस्तुएं

332. **श्री नागमणि:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न विमानपत्तनों से 1 जनवरी से 30 नवम्बर, 1995 के बीच जब्त की गयी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन वस्तुओं को बेच दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जब्त की गयी वस्तुओं के निपटान हेतु सामान्यतः अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) से (ख) पहली जनवरी से 30 नवम्बर, 1995 तक की अवधि के दौरान देश में अन्तरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर 92.83 करोड़ रुपये मूल्य का सोना चांदी, विदेशी मुद्रा, कैमरे, वी०सी०आर०, सर्प चर्म, स्वापक औषध द्रव्य, बहुमूल्य रत्न, घड़ियां और घड़ियों के पुर्जे, कम्प्यूटर के पुर्जे, सेलुलर फोन आदि पकड़े गये थे। इसी अवधि के दौरान विमानपत्तनों पर पकड़े गये और/या जब्त किये गये 101.08 करोड़ रुपये के माल को बेचा गया।

पकड़े गये माल को सामान्यतः जब्ती संबंधी कार्यवाहियों के पूरा हो जाने पर बेच दिया जाता है। किन्तु शीघ्र खराब होने वाले तथा ज्यादा देर तक न रखे जा सकने वाले माल का अभिग्रहण करने के बाद शीघ्र ही निपटान कर दिया जाता है।

जब्तशुदा उपभोक्ता माल को, जो निपटान के लिए तैयार पड़ा होता है, सीमाशुल्क के काउंटरों पर अथवा राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ और उपभोक्ता सहकारी

समितियों के माध्यम से खुदरा बिक्री द्वारा निपटाया जाता है। बल्कि व्यापारिक माल की या तो नीलामी की जाती है अथवा निविदाएं आमंत्रित करके बेचा जाता है, जबकि जोखिमपूर्ण और खतरनाक माल को मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार नष्ट कर दिया जाता है। सोने को बम्बई सीमाशुल्क गृह में खुदरा काउंटर के जरिए बेचा जाता है और चांदी को चार बड़े सीमाशुल्क गृहों अर्थात् बम्बई, कलकत्ता दिल्ली और मद्रास स्थित खुदरा काउंटरों के जरिए बेचा जाता है। उपभोक्ता माल के मामले में निपटान मूल्य इस रयोजन के लिए गठित की गयी मूल्यांकन समिति द्वारा निश्चित किया जाता है। गैर-उपभोक्ता माल के संबंध में मूल्य नीलामी / निविदा द्वारा निश्चित किया जाता है। सोने और चांदी को उस मूल्य पर बेचा जाता है जो बम्बई में इन वस्तुओं के बाजार मूल्य से जुड़ा होता है।

Constitution of a Board to Monitor Capital Investment at District level

*333. SHRIMATI SUSHMA SWARAJ:
SHRI RAM JETHMALANI:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are considering a proposal for constituting a board to monitor capital investment being made at district level in the country;

(b) if so, the details thereof;

(c) if not, whether it is a fact that as a result of a campaign for internal external capital investment started at extensive level during the past few years in the country, a wide gap in the development of different regions is being created; and

(d) if not, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) and (b) Government at present do not have such a proposal.

(c) and (d) Domestic and Foreign Capital investment channeled through the Private Sector are largely based on economic considerations such as availability of market, infrastructure including communication facilities, technical and skilled manpower etc. Private Sector investments are not directed by Government to specific locations but there are fiscal incentives for investment in backward states. In addition through the machinery of the Planning Commission, as well through the system of State and district level planning, efforts are made to achieve the objective of balanced regional economic development and to minimise regional disparities.

Private Power projects

*334. SHRI S. MUTHU MANI: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that estabilishing mega power projects based on imported coal is a feasible option; and

(b) whether Government are considering to establish a central organisation to co-ordinate with private power projects and State Electricity Boards for proper distribution of power generated in the private power sector among the State Electricity Boards?

THE MINISTER OF POWER (SHRI N.K.P. SALVE): (a) Yes, Sir, subject to the techno-economic viability of the project.

(b) No, Sir.

ग्रामीण संस्कृति पर आधारित धारावाहिकों का निर्माण

*335. **श्री रामदेव भंडारी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन पर दिखाए जा रहे धारावाहिकों का निर्माण शहरी दर्शकों को ध्यान में रखकर किया जाता है और इसलिए उनमें भारत के मध्यम तथा उच्च वर्ग के पश्चिमी सभ्यता के नकल वाले रहन-सहन को दर्शाया जाता है;

(ख) क्या ग्रामीण परिवेश पर आधारित धारावाहिकों का निर्माण धीरे-धीरे कम होता जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसके परिणामवरूप भारत की